फैक्टरियों में विस्तार के लिये आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिये 10 सदस्यों की एक नई समिति गठित की है।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा लाइसेंस देने के लिये क्षमता की चरणबद्ध उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सामति लंबित आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिये समय समय पर अपनी बैठक बुलायेगी।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में 30-9-91 तक नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु लंबित प्रस्तावों की सूची उपाबंध पर है। जांच समिति/लाइसेंसिंग समिति द्वारा इन आवेदन पत्रों की संशोधित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संवीक्षा की जायेगी।

[देखिये परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 16]

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में उत्तर दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालय

840. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये क्या मापदंड हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जो इन मापदंडों को पूरा करते हैं परन्तु वहां पर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है; और

(ग) वहां पर कब तक ऐसे विद्यालयों के खोले जाने और उनके लिये भवन निर्माण कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) देश भर में प्राईमरी स्कूलों को खोलने के लिये कोई सख्त मानदंड नहीं बनाये गये हैं। केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि 300 की जनसंख्या (मरूस्थलीय, जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 200) वाली सभी बस्तियों में एक-एक प्राईमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिये और सभी बच्चों को उनके निवास स्थान से एक कि०मी० की दूरी के अन्दर ही प्राईमरी शिक्षा की सुविधा व्यवस्था करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। प्रत्येक राज्य अपनी जरूरतों एवं नीति के अनुसार मानदंड निर्धारित करता है और प्राईमरी स्कूलों को खोलने और भवनों के निर्माण के संबंध में भी स्वयं ही निर्णय लेता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक की जनसंख्या वाली लगभग 14,300 बस्तियों में प्राईमरी स्कूल नहीं हैं।

Literacy rate in Arunachal Pradesh

841. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the present rate of literacy in Arunachal Pradesh, districtwise; and

(b) what steps Government have taken so far to increase the percentage of literacy in that States indicating the expenditure incurred for the purpose during the last two years?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) According to 1991 census, the provisional literacy rate in the state of Arunachal Pradesh for the population aged 7 years and above is 41.22%. The literacy rate for the districts of Arunachal Pradesh cannot be calculated till the popualtion in the age-group 0-6 is tabulated. However, the position regard-

ing total population and literates (7 years and above) in different districts in the state of Arunachal Pradesh, according to 1991 census is as under:

Sl. No.	Name of the district	Total population	Literates (7 years and above)
1	Tawang	27,574	6,860
2	West Kameng	56,402	20,348
3	East Kameng	50,238	10,260
4	Lower Subansiri	154,591	50,614
5	Upper Subansiri	49,163	14,599
6	West Siang	89,778	32,292
7	East Siang;	99,985	35,782
8	Dibang Valley	42,928	16,218
9	Lohit	109,632	43,358
10	Changlang	97,891	31,045
11	Tirap	85,210	20,771

(b) Universalisation of elementary education including non-formal education and the National Literacy Mission which aims at imparting functional literacy to 80.00 million adult illiterates in the 15-35 age-group by 1995 form an integral part of a larger programme for eradication of illiteracy in the country, including the State of Arunachal Pradesh. The expenditure incurred during the last two years on these programmes in the State of Arunachal Pradesh was as under:

(*Rs. in lakhs*)

Year	Expenditure in the Central Sector	Expenditure in the State Sector
1989-90	89·14	1815·00
1990-91	97·34	2017·00 (anticipated)

Golden Jubilee of Quit India Movement

842. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to celebrate the Golden Jubilee of 1942 Quit India Movement; and

(b) if so, what are the details thereof including the formulation of committee and programmes earmarked for celebration?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A National Committee to oversee the Celebrations has been drawn up. It will convene in the near future to suggest programmes.